

योगी का आदेश आया, रातोंरात 2500 अवैध मदरसे गायब

मदरसों और वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच के आदेश से हड़कंप : राज खुलने के डर से धड़ाधड़ गिरने लगे अवैध मदरसों के शर्टर



राकेश सिंह

उत्तरप्रदेश में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनकी आड़ में यहाँ हजारों अवैध मदरसे भी संचालित हो रहे हैं।

उत्तरप्रदेश में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनकी आड़ में यहाँ हजारों अवैध मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। उन्हें जमीन खा गयी या आसमान निगल गया, पता नहीं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये मदरसे सरकारी लाभ भी ले रहे थे। इन्हें अधिकारिक मदरस, मूलविलियों को तन्हवा और पढ़ानेवालों को वजीफा भी मिल रहा था, मतलब सरकारी खजाने की पूरी लूट मची हुई थी। जांच के दौरान ये भी खुलासे हो रहे हैं कि ज्यादा ग्राउं पार्क के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों में भी शिक्षकों और छात्रों की संख्या में हेरा-फेरी की गयी है। यह तो हुई सामान्य बात। इन मदरसों में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आ रही है और जिससे मदरसों को संचालित करनेवाले ज्यादा खोफजादा हैं, वह है सोसं ऑफ फंड। मदरसावाले कह रहे हैं कि मदरसों को वे दान के पैसों

मदरसे गायब हो गये।

उत्तरप्रदेश में कुल 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनकी आड़ में यहाँ हजारों अवैध मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। उन्हें जमीन खा गयी या आसमान निगल गया, पता नहीं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ये मदरसे सरकारी लाभ भी ले रहे थे। इन्हें अधिकारिक मदरस, मूलविलियों को तन्हवा और पढ़ानेवालों को वजीफा भी मिल रहा था, मतलब सरकारी खजाने की पूरी लूट मची हुई थी। जांच के दौरान ये भी खुलासे हो रहे हैं कि ज्यादा ग्राउं पार्क के लिए मान्यता प्राप्त मदरसों में भी शिक्षकों और छात्रों की संख्या में हेरा-फेरी की गयी है। यह तो हुई सामान्य बात। इन मदरसों में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आ रही है और जिससे मदरसों को संचालित करनेवाले ज्यादा खोफजादा हैं, वह है सोसं ऑफ फंड। मदरसावाले कह रहे हैं कि मदरसों को वे दान के पैसों

मदरसों को 50 प्रतिशत फंडिंग सीक्रेट सोसेज से आती है।

ये सीक्रेट सोसे कौन हैं, वह अब बताना पड़ेगा। योगी सरकार अब इन सोसेजों की भी जांच करेंगी कि कहाँ यह फंड आतंकी संगठनों से तो नहीं आ रहा। विदेशों से जो दान आ रहा है, उसे कौन दे रहा है। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच होगी। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश भी रद्द कर दिया। 7 अप्रैल, 1989 को बाद से आज तक वक्फ बोर्ड ने कैसे जमीन हड़पी है और कैसे हजारों मदरसे कागजों पर उग आये थे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।

मदरसे की आय का स्रोत क्या है? अग्र छात्र अन्य जगह भी नामांकित हैं, तो उसकी जानकारी ली जा रही है? अग्र सरकारी समूह या संस्था से मदरसों की संबद्धता है, तो उसका विवरण दें?

जाहिर है इन सारे सवालों का जवाब तो हजारों की संख्या में चल रहे मदरसों के पास नहीं ही होगा। मदरसों की हालत क्या है, वह योगी से छिपा नहीं है। ज्यादातर मदरसों में बस नाम की हिंदी, झिंगारी और मैथूर पढ़ाई जाती है। यहाँ के बच्चे प्रधानांगी और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाते। अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग तो छोड़ ही जीजए। ऐसे मदरसों के बच्चों से बातबात करेंगे तो वे बतायेंगे कि उनको मदरसे में हिंदी, झिंगारी, मैथूर, साइंस सब पढ़ाया जाता है। लेकिन जब उन्हें इन सबजेक्ट के जुड़े साल पुराने का शब्द नहीं है। खालीपाने का जाहिर है कि यह अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया जायेगा। इस आदेश के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर सीधी मामलों का पुनर्परिक्षण की भी करवाया जायेगा। इस आदेश के बाद मदरसा के संचालकों को कुछ राजनीतिक दलों और कुछ स्वयंभू नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जाहिर है, इसकी आड़ में हजारों-हजार एकड़ सरकारी जमीन की लूट हुई है और गलत तरीके से फंड भी इकट्ठा किया गया है। 1989 के बाद से आज तक वक्फ बोर्ड ने कैसे जमीन हड़पी है और कैसे हजारों मदरसे कागजों पर उग आये थे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।

मदरसे की आय का स्रोत क्या है? अग्र छात्र अन्य जगह भी नामांकित हैं, तो उसकी जानकारी ली जा रही है? अग्र सरकारी समूह या संस्था से मदरसों की संबद्धता है, तो उसका विवरण दें?

जाहिर है इन सारे सवालों का जवाब तो हजारों की संख्या में चल रहे मदरसों के पास नहीं ही होगा। मदरसों की हालत क्या है, वह योगी से छिपा नहीं है। ज्यादातर मदरसों में बस नाम की हिंदी, झिंगारी और मैथूर पढ़ाई जाती है। यहाँ के बच्चे प्रधानांगी और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाते। अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग तो छोड़ ही जीजए। ऐसे मदरसों के बच्चों से बातबात करेंगे तो वे बतायेंगे कि उनको मदरसे में हिंदी, झिंगारी, मैथूर, साइंस सब पढ़ाया जाता है। लेकिन जब उन्हें इन सबजेक्ट के जुड़े साल पुराने का शब्द नहीं है। खालीपाने का जाहिर है कि यह अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया जायेगा। इस आदेश के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर सीधी मामलों का पुनर्परिक्षण की भी करवाया जायेगा। इस आदेश के बाद मदरसा के संचालकों को कुछ राजनीतिक दलों और कुछ स्वयंभू नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जाहिर है, इसकी आड़ में हजारों-हजार एकड़ सरकारी जमीन की लूट हुई है और गलत तरीके से फंड भी इकट्ठा किया गया है। 1989 के बाद से आज तक वक्फ बोर्ड ने कैसे जमीन हड़पी है और कैसे हजारों मदरसे कागजों पर उग आये थे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।

मदरसे की आय का स्रोत क्या है? अग्र छात्र अन्य जगह भी नामांकित हैं, तो उसकी जानकारी ली जा रही है? अग्र सरकारी समूह या संस्था से मदरसों की संबद्धता है, तो उसका विवरण दें?

जाहिर है इन सारे सवालों का जवाब तो हजारों की संख्या में चल रहे मदरसों के पास नहीं ही होगा। मदरसों की हालत क्या है, वह योगी से छिपा नहीं है। ज्यादातर मदरसों में बस नाम की हिंदी, झिंगारी और मैथूर पढ़ाई जाती है। यहाँ के बच्चे प्रधानांगी और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाते। अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग तो छोड़ ही जीजए। ऐसे मदरसों के बच्चों से बातबात करेंगे तो वे बतायेंगे कि उनको मदरसे में हिंदी, झिंगारी, मैथूर, साइंस सब पढ़ाया जाता है। लेकिन जब उन्हें इन सबजेक्ट के जुड़े साल पुराने का शब्द नहीं है। खालीपाने का जाहिर है कि यह अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया जायेगा। इस आदेश के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर सीधी मामलों का पुनर्परिक्षण की भी करवाया जायेगा। इस आदेश के बाद मदरसा के संचालकों को कुछ राजनीतिक दलों और कुछ स्वयंभू नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जाहिर है, इसकी आड़ में हजारों-हजार एकड़ सरकारी जमीन की लूट हुई है और गलत तरीके से फंड भी इकट्ठा किया गया है। 1989 के बाद से आज तक वक्फ बोर्ड ने कैसे जमीन हड़पी है और कैसे हजारों मदरसे कागजों पर उग आये थे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।

मदरसे की आय का स्रोत क्या है? अग्र छात्र अन्य जगह भी नामांकित हैं, तो उसकी जानकारी ली जा रही है? अग्र सरकारी समूह या संस्था से मदरसों की संबद्धता है, तो उसका विवरण दें?

जाहिर है इन सारे सवालों का जवाब तो हजारों की संख्या में चल रहे मदरसों के पास नहीं ही होगा। मदरसों की हालत क्या है, वह योगी से छिपा नहीं है। ज्यादातर मदरसों में बस नाम की हिंदी, झिंगारी और मैथूर पढ़ाई जाती है। यहाँ के बच्चे प्रधानांगी और मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं बता पाते। अंग्रेजी के शब्दों की स्पेलिंग तो छोड़ ही जीजए। ऐसे मदरसों के बच्चों से बातबात करेंगे तो वे बतायेंगे कि उनको मदरसे में हिंदी, झिंगारी, मैथूर, साइंस सब पढ़ाया जाता है। लेकिन जब उन्हें इन सबजेक्ट के जुड़े साल पुराने का शब्द नहीं है। खालीपाने का जाहिर है कि यह अप्रैल 1989 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर, भीटा, ऊसर आदि भूमि का इस्तेमाल वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया जायेगा। इस आदेश के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर सीधी मामलों का पुनर्परिक्षण की भी करवाया जायेगा। इस आदेश के बाद मदरसा के संचालकों को कुछ राजनीतिक दलों और कुछ स्वयंभू नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। जाहिर

संपादकीय

ऐसे तराशेंगे टैलंट!

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 200 से ज्यादा अंडर 17 विभिन्न काबड़ी प्लेयर्स को जिस तरह से जेंट्स टॉयलेट में रखा खाना परोसा गया, वह देश में खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकारी तंत्र के शर्मनाक रवैये को उजारा रहा। हालांकि विडियो वायरल होने और इसकी खबरें मैटडियो में अनेके बाद कार्रवाई में देर नहीं की गयी। तत्काल स्पोर्ट्स अफिसर्स को निलंबित करने और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच के भी आदेश जारी कर दिये गये, लेकिन यह कार्रवाई न तो इस प्रकरण से हुए नुकसान की भरपाई करती है और न ही इस तरह के रवैये का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण पेश कर पाती है। अगर यह घटना इस तरह मिठाई में नहीं आती या इसके विडियो वायरल न हुए होते तो महिला काबड़ी प्लेयर्स के साथ ऐसा बहुत रक्खने वाले लोगों में किसी को भी आपाध भाव आता या प्रशासन के आता अधिकारियों में से कोई इसे नोटिस में लेता। ऐसी धारणा का कारण यह है कि अपने देश में खिलाड़ियों की उपेक्षा कोई नवी बात नहीं है खेल तंत्र, प्रशासन और सत्ता से जुड़े लोग खुद को इन खिलाड़ियों की किस्मत का शहंशाह मानते हैं। उनकी यह भावना कभी किसी महिला खिलाड़ी के बीच शाश्चरण की खबर के रूप में समझे आती है, तो कभी खिलाड़ियों को उपतिथियों को अनदेखा करने और आयोजनों के दौरान उन्हें अहमियत न दिये जाने के रूप में। इसी रवैयाको कोलाकाता में डुरंड कप फाइनल के बाद ट्रॉफी देते समय विजेता टीम के कप्तान सुनील छेत्री को जिस तरह से साइड करने की कोशिश की गयी, वह खेलों और खिलाड़ियों के दौरान उन्हें अहमियत न दिये जाने के अधिकारियों को बताता है। आश्वस्त्री की बात यह है कि सत्ता का यह नजरिया तब है, जब खुद प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों को आओ बढ़ाने की हर मुकाबिन कोशिश में जुटे जर आते हैं। वह न केवल महत्वपूर्ण मुकाबलों से पहले निजी तौर पर खिलाड़ियों की हैसला अफजाई करते हैं, बल्कि मुकाबले के बाद भी उनसे मिल कर अलग-अलग तरीकों से सार्वजनिक तौर पर उनका उत्साह बढ़ाते हुए दिखते हैं। इसका एक मकसद व्यापक तौर पर यह संदेश देना भी है कि देश अपने इन खेल प्रतिभाओं की रखवाह करता है, उनका सम्मान करता है। इस बीच कई ऐसी योजनाएं भी लायी गयीं जिनसे ग्रासरूट लेवल पर टैलेट को फहारने और मांजने में मदद मिले। इन सबका पॉर्जिंटिव अपर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन पर भी देखा जा रहा है, लेकिन ये सब प्रतीकात्मक उपाय बन कर रह जायेंगे, अगर देश में उन्हें तक खिलाड़ियों को लेकर खेल तंत्र का रखवाह नहीं बदलता। अरिहंत किसी भी अच्छी स्क्रीन लायी जाये उसका क्रियान्वयन तो इसी त्रैं के जरिए होना है। जरूरी है कि इस रखवाह में थायी सुधार के दूरगामी उपाय किये जायें।

अगर यह घटना इस तरह नीटिया ने नहीं आती या इसके विडियो वायरल न हुए होते तो महिला काबड़ी प्लेयर्स के साथ ऐसा बहुत करने वाले लोगों में से किसी के नीं मन में शाद ही कोई अपाध भाव आता या प्रशासन के आता अधिकारियों में से कोई इसे नोटिस में लेता।

के प्रति सत्तांशीओं के नजरिये को बताता है। आश्वस्त्री की बात यह है कि सत्ता का यह नजरिया तब है, जब खुद प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों को आओ बढ़ाने की हर मुकाबिन कोशिश में जुटे जर आते हैं। वह न केवल महत्वपूर्ण मुकाबलों से पहले निजी तौर पर खिलाड़ियों की हैसला अफजाई करते हैं, बल्कि मुकाबले के बाद भी उनसे मिल कर अलग-अलग तरीकों से सार्वजनिक तौर पर उनका उत्साह बढ़ाते हुए दिखते हैं। इसका एक मकसद व्यापक तौर पर यह संदेश देना भी है कि देश अपने इन खेल प्रतिभाओं की रखवाह करता है, उनका सम्मान करता है। इस बीच कई ऐसी योजनाएं भी लायी गयीं जिनसे ग्रासरूट लेवल पर टैलेट को फहारने और मांजने में मदद मिले। इन सबका पॉर्जिंटिव अपर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन पर भी देखा जा रहा है, लेकिन ये सब प्रतीकात्मक उपाय बन कर रह जायेंगे, अगर देश में उन्हें तक खिलाड़ियों को लेकर खेल तंत्र का रखवाह नहीं बदलता। अरिहंत किसी भी अच्छी स्क्रीन लायी जाये उसका क्रियान्वयन तो इसी त्रैं के जरिए होना है। जरूरी है कि इस रखवाह में थायी सुधार के दूरगामी उपाय किये जायें।

अभिमत आजाद सिपाही

भारत का अस्तित्व एक सेव्यूलूर देश के रूप में शुरू से रहा है, यहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। इसलिए यह देश साप्रादायिक साजिश का शिकार नहीं हो सकता। वसुष्ठै कुटुंबकर्म के संस्कार और सर्वे भवतु सुखिनः के संकल्प का ही नीतीजा है कि भारत में दुनिया के सभी धर्मावलंबी समानता, स्वतंत्रता और समावेशी माहौल में रहकर फल-फूल रहे हैं। 2014 से ही प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली माजपा सरकार देश के अल्पसंख्यक साजिश का शिकार नहीं हो सकता।

मोदी सरकार का प्रयास अल्पसंख्यकों का विकास



डॉ मिस्कीका हस्म

2014 के बाद पिछले आठ वर्षों में नंदेंद्र मोदी की सरकार के धेदभाव रहित विकास के संकल्प ने अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों के विकास में बराबर का विस्सेस्वार एवं भागीदार बनाया है। यही विश्वास और विकास का माहौल भारत विशेषी तत्वों की बेचैनी का कारण है। भारत का अस्तित्व एक सेव्यूलूर देश के रूप में शुरू से रहा है, यहां गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिलती है। इसलिए यह देश साप्रादायिक साजिश का शिकार नहीं हो सकता।

वसुष्ठै कुटुंबकर्म के संस्कार और सर्वे भवतु सुखिनः के संकल्प का ही नीतीजा है कि भारत में दुनिया के सभी धर्मावलंबी समानता, स्वतंत्रता और समावेशी माहौल में रहकर फल-फूल रहे हैं।

2014 से ही प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश के अल्पसंख्यक वर्गों के विकास, सामाजिक न्याय और उन्हें देश की मुख्याधारा से जोड़ने का काम कर रही है।

भाजपा पर

2014 से ही प्रधानमंत्री नंदेंद्र मोदी के विकास के संकल्प का निर्देश देने के लिए वाली भाजपा सरकार देश के अल्पसंख्यक वर्गों के विकास, सामाजिक न्याय और मुख्याधारा से जोड़ने का काम करता है।

के साथ नवी मजिल, हुनरहाट

और उत्ताद जैसी योजनाओं से उनके

सर्वांगीण विकास का प्रयास किया है।

मुस्लिम महिलाओं के साथ होने

वाले वाले अन्यान्यों की समाजिक

केन्द्रीय भूमि के लिए भाजपा

क

धनबाद/बोकारो/बेरमो

भाजपा झारखण्ड की सभी सीटों पर हासिल करेगी शानदार जीत : लक्ष्मीकांत वाजपेयी



बोकारो (आजाद सिपाही)। झारखण्ड भाजपा के एप्रेसी बनाए जाने के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहली बार सप्तिवार गृहस्थार को देखाएं, दुमगां, जमताड़ा व धनबाद होते पहुंच बोकारो पहुंचे। तेलमाटो ब्रिज पर भरत यादव के नेतृत्व में पाठी नेताओं-कार्यकारी ने पृष्ठ गृह भेंट कर उत्कर गर्मजांशी से स्वतंत्र किया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर कार्यकारी ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत व अभिनन्दन किया। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी- सांसद पश्चिमांश सिंह- मुख्य संसदीकारी सह बोकारो विधायिका विरुद्ध नारायण, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, पूर्व मंत्री छत्रपति महाते में पौधा रोपण किया। साथ ही प्रदेश प्रभारी ने कार्यकारी से संवाद स्थापित कर संगठन को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिए जाने की बात की, ताकि पड़ित दीनदयाल उपाध्याय और शयाम प्रसाद मुख्यों के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि मैं घुटान टेक कर संगठन के लिए काम करूँगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा झारखण्ड की सभी सीटों पर शानदार जीत हासिल करेगी।

गोमिया विधायक लंबोदर महतो को पत्र सौंपकर सड़क बनवाने की मांग

ललपनिया

(आजाद सिपाही)

उग्रवाद प्रभावित गोमिया

प्रखण्ड क्षेत्र के

तिनैया ग्राम

पंचायत अंतर्गत

दिनिया से हलवे



गंग तल लगभग पांच किलोमीटर लंबी सड़क का अतिशीघ निर्माण करने की मांग को लेकर गृहस्थार को विधायक लंबोदर महतो को पत्र सौंप गया। इसके अलावा बोकारो जो पृथक् अध्यक्ष सुवीता देवी, प्रखण्ड विकास पराधिकारी कपिल कुमार, जीप संदर्भ डॉ सुरेंद्र राज को भी प्रतिनिधि भेजा गया है। पत्र सौंपने के बाद गोमिया विधायक सभा प्रभारी कुम्ही सेना सह आजसू के बेता पंकज कुमार वाधीरी ने विधायक को समस्या से अवगत कराया। कहा कि तिलाया पंचायत के राजस्व ग्राम हलवे में 300 तक सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। जबकि इस गंग में ग्रामीणों की सर्खा की रीवा 300 तक जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। पत्रके सड़क के अभाव से ग्रामीण पंचायत से अवगत कराया। कहा कि तिलाया पंचायत के राजस्व ग्राम हलवे में 300 तक सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। जबकि इस गंग में ग्रामीणों की सर्खा की रीवा 300 तक जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है।

झारखण्ड पुलिस में एसोसिएशन की बोकारो शाखा का चुनाव कराने को लेकर डीआइजी को लिखा पत्र

बोकारो (आजाद सिपाही)। झारखण्ड

पुलिस में एसोसिएशन बोकारो शाखा

का चुनाव कराने के संबंध में पुलिस उप

महानिया कुम्ही लगभग संसदीय

प्रखण्ड अध्यक्ष दशरथ हेंड्रेन, शिक्षक तुलसी बेसरा, सुरेण बेसरा, सुनील

कुमार, देवालाल कुमार और नरेश बेसरा आदि उपस्थित थे।



गंग तल लगभग पांच किलोमीटर लंबी सड़क का अतिशीघ निर्माण करने की मांग को लेकर गृहस्थार को विधायक लंबोदर महतो को पत्र सौंप गया। इसके अलावा बोकारो जो पृथक् अध्यक्ष सुवीता देवी, प्रखण्ड विकास पराधिकारी कपिल कुमार, जीप संदर्भ डॉ सुरेंद्र राज को भी प्रतिनिधि भेजा गया है। पत्र सौंपने के बाद गोमिया विधायक सभा प्रभारी कुम्ही सेना सह आजसू के बेता पंकज कुमार वाधीरी ने विधायक को समस्या से अवगत कराया। कहा कि तिलाया पंचायत के राजस्व ग्राम हलवे में 300 तक सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। जबकि इस गंग में ग्रामीणों की सर्खा की रीवा 300 तक जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। पत्रके सड़क के अभाव से ग्रामीण पंचायत से अवगत कराया। कहा कि तिलाया पंचायत के राजस्व ग्राम हलवे में 300 तक सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है। जबकि इस गंग में ग्रामीणों की सर्खा की रीवा 300 तक जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है।

सीआइएसएफ ने चलाया छापामारी अभियान, 17 टन अवैध कोयला जब्त

झारखण्ड सिपाही

पर लगभग क्षेत्र के लेकर

जिला पुलिस प्रशासन की

लगातार कार्रवाई के बीच

सीआइएसएफ ने भी मार्ग

मनोनीत है और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं हो रहा है कि बोकारो जिला एसोसिएशन का कार्यकाल तीन वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। यहां एसोसिएशन के लगभग सभी सदस्य

मनोनीत हैं और अपने प्रभाव का उपयोग कर पुलिस में

एसोसिएशन शाखा, बोकारो के चुनाव कराने के बीच दिया जा रहा है। इस कारण बोकारो जिला में पुलिस कल्पना कार्य का निष्पादन नहीं ह

